निजीकरण के खिलाफ उ०प्र० बिजली कर्मियों का संघर्ष

यह जीत तात्कालिक है, खतरा बरकरार है !

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का विघटन कर तीन निगमों में तब्दील कर देने के निर्णय के खिलाफ विद्युत अभियन्ताओं और कर्मचारियों की ग्यारह दिन तक चली शानदार हड़ताल के आगे अन्ततः सरकार को झुकना पड़ा। हड़ताली नेताओं और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते में सरकार को निजीकरण का निर्णय अगले एक वर्ष तक टाल देना पड़ा है। हड़ताली नेताओं-कर्मचारियों पर थोपे गये रासुका, एस्मा आदि सभी कानूनों को वापस लेने, सभी बर्खास्त कर्मचारियों-अभियन्ताओं को वापस काम पर रखने एवं किसी भी प्रकार की दण्डात्मक कार्रवाई न करने का आश्वासन देने के बाद ही हड़ताल वापस ली गयी।

उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों की यह तात्कालिक जीत इस बात का प्रमाण है कि यदि किसी संघर्ष को अस्तित्व का सवाल बनाकर लड़ा जाये, जुझारू एकजुटता बरकरार रहे तो दमन-उत्पीड़न के हर प्रहार को झेलते हुए भी अन्ततः कामयाबी हासिल की जा सकती है। इस जीत का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि उदारीकरण-निजीकरण की नीतियों के खिलाफ पूरे देश के भीतर चलीं अधिकांश लड़ाइयों को दुःखद पराजय का मुंह ही देखना पड़ा है। यह जीत आगे के लिए एक मिसाल बन सकती है, यदि इसकी उपलब्धियों को बचाये रखा जाता है।

दरअसल, बिजली कार्मियों ने अपनी लड़ाई पूर्व की लड़ाइयों की तुलना में ज्यादा हठी ढंग से इसलिए लड़ी क्योंकि देश में विगत एक दशक के निजीकरण-उदारीकरण के अनुभवों ने उन्हें काफी कुछ सिखा दिया था। एक तो यह कि निजीकरण के नतीजे अब खुलकर सामने आ चुके हैं और दूसरे यह कि आधू-अधूरे मन से लड़ी गयी लड़ाइयों का हश्र भी वे देख चुके थे। इसलिए, ज्यादा अडिग ढंग से उन्होंने एकजुटता दिखायी और इसीलिए जीतने का संकल्प लेकर लड़ रहे थे।

15 जनवरी 2000 से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल को कुचलने के लिए सरकार ने हरमुमकिन हथकण्डे अख्तियार किये। हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए सरकार ने कर्मचारियों को यह झूठा आश्वासन दिया कि नये बने निगमों में उनकी सेवा शर्तों एवं अन्य सुविधाओं में कोई कटौती और छंटनी नहीं की जायेगी। लेकिन विद्युतकर्मी हरियाणा, आन्ध्रप्रदेश और उड़ीसा के अनुभव देख चुके थे, जहां कर्मचारियों की छंटनी कर दी गयी और सेवाशर्तें कड़ी बना दी गयी थीं। इसलिए, वे सरकारी झांसे में नहीं आये। जब सरकार हड़ताल रोकने में नाकाम रही तो फिर उसने हमलावर तेवर अख्तियार किया। प्रदेश के हेंकड़ीबाज ऊर्जा मंत्री नरेश अग्रवाल ने रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) और आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम (एस्मा) लगा कर गिरफ्तार करने और नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी देनी शुरु की और बाद में अमल भी किया। सैकड़ों नेताओं और हजारों कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। दर्जनों पर रासुका एवं एस्मा ठोंक दिया गया। दर्जनों अभियन्ताओं एवं हजारों कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया एवं नयी भर्तियां शुरू कर बेरोजगार अप्रैण्टिसों के सपनों के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया गया। इसके साथ ही, सरकार ने आम जनता को बरगलाने के लिए अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापनों के जरिये हड़ताल को राष्ट्रद्रोह घोषित कर और फर्जी आंकड़ों को छापकर, नित नये-नये झूठ गढ़कर गोएबल्स (हिटलर का प्रचार मंत्री, जो कहता था कि बार-बार प्रचार करके झूठ को भी सच में तब्दील किया जा सकता है) के प्रचार को भी पीछे छोड़ दिया। इन विज्ञापनों में और प्रदेश के मंत्रियों के बयानों में राज्य विद्युत परिषद के तथाकथित घाटे के लिए कर्मचारियों के निकम्मेपन व भ्रष्टाचार को दोषी ठहराया जाता था। हड़ताली नेताओं ने सरकारी प्रचार को भी चुनौती दी और इस मुद्दे पर आमने-सामने बहस के लिए ललकारा।

सरकार ने हड़ताल तोड़ने के लिए पुलिस को छुट्टा सांड़ों की तरह आतंक फैलाने के लिए अनौपचारिक [illegible] हरी झण्डी दे दी थी। नतीजा यह हुआ कि गिरफ्तारी के नाम पर पुलिस ने आधी रात को हड़ताली नेताओं के घरों पर दस्तक देना शुरू की और उनकी पत्नियों-बेटियों को बेइज्जत किया, बच्चों को आतंकित किया। लेकिन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे कर्मचारियों के परिवारों की स्त्रियों ने भी सड़कों पर मोर्चा सम्हाल लिया।

केन्द्र सरकार ने भी राज्य सरकार को हड़ताल कुचलने के लिए पूरा समर्थन और सहयोग दिया। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री कुमारमंगलम लखनऊ दौरे पर आये और सरकार की पीठ थपथपाने के बाद दिल्ली लौटकर बयान दिया कि पालिसी (नीति) के सवाल पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इसी तर्ज पर नरेश अग्रवाल भी मगरूरियत से बयान देते रहे कि परिषद के विघटन के निर्णय के अतिरिक्त वे किसी भी चीज पर वार्ता करने को तैयार हैं।

लेकिन, जैसे-जैसे दमन बढ़ता गया, आन्दोलन और भी जोर पकड़ता गया। उत्तरी ग्रिड के अभियन्ताओं और छह राज्यों के बिजली कार्मियों ने भी समर्थन में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की और दमन जारी रहने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी। अन्ततः बात बिगड़ती देखकर कई चक्र की वार्ताओं के बार सरकार को झुकना पड़ा और बिजली कर्मी अपने संघर्ष में कामयाब हो गये।

लेकिन, बिजली कार्मियों की यह जीत स्थायी नहीं है। खतरा अभी सिर्फ साल भर तक टला है। इस अवधि को उन्हें अपनी एकता को मजबूत बनाने और भावी संघर्ष की तैयारी के रूप में लेना होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की ढिलाई महंगी पड़ सकती है।

इस आन्दोलन का सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि यदि आम कर्मचारी एक जुट हों, संकल्पबद्ध हों और चौकस हों तो अवसरवादी नेतृत्व को भी साथ खींचा जा सकता है। लेकिन, साथ ही, नए जुझारू नेतृत्व को भी साहस के साथ आगे आने की जरूरत है।

● विजय शंकर तिवारी